



खिलाड़ियों से जुड़ी है प्रदेश की भावनाएं : मुख्यमंत्री

सरकार ने 2.08 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 25 मार्च, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिन्टन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, वर्ष 2020-21 के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ी चन्दन सिंह को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। देवभूमि उत्तराखण्ड ट्रोगाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिन्टन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन, वर्ष 2020-21 के लिए ताईक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी, एवं वर्ष 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए जाने पर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2021-22 से एथलेटिक्स खिलाड़ी सुरेश चन्द्र पाण्डे को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों एवं 42 प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। खिलाड़ियों

एवं प्रशिक्षकों को कुल 2.08 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर एवं पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा होता है, तो पूरे देश की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं।

राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में "मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना" प्रारंभ की गई है। प्रत्येक जिले के 150 बालक और 150 बालिकाओं अर्थात् प्रदेश के कुल 3900 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है।

खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक साल में खेल के क्षेत्र में अनेक निर्णय लिये हैं। राज्य में नई खेल नीति बनाई गई, जिसमें खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जा रही है। पारंपरिक खेलों को भी खेल नीति में जोड़ा



है। राज्य के 8 से 14 साल के 3900 बच्चों को प्रतिमाह 1500 रुपये की धनराशि

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत दी जा रही है। 2024 में

38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखण्ड करेगा।

स्वयं सहायता समूहों को बनाने का उद्देश्य आजीविका प्रदान करना : मुख्य सचिव

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 25 मार्च, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह सृजित कर क्लस्टर आधारित रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को कार्यों का परिसीमन न करके पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों को मात्र उत्पादन और वितरण जैसे कार्यों में न लगा कर सर्विस सेक्टर से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बनाने का उद्देश्य आजीविका प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में बहुत से उत्पाद अन्य बाहरी राज्यों से आयातित किए जा रहे हैं। ऐसे उत्पादों को चिन्हित कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित कर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। साथ ही उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर उत्पादों में विविधता लायी जानी चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने हेतु की जा रही गुड प्रैक्टिसेज का अध्ययन कर प्रदेश में लागू किए जाने की



दिशा में भी कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों और इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराए जाने पर विचार अवश्य किया जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने हेतु मार्केटिंग, बाजार उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उत्पादों का संग्रहण और ट्रांसपोर्टेशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पिरुल के

ब्रिकेट्स को खाना बनाने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके उत्पादन और वितरण में स्वयं सहायता समूहों की सहायता लेकर इस योजना का संचालित किया जा सकता है। इससे एक और जहां जंगलों से पिरुल हटाकर जंगलों को जलने से बचाया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी एवं डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम सहित सम्बन्धित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने की मसूरी पेयजल एवं सीवर लाइन सहित मसूरी के सौंदर्यीकरण एवं विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में मसूरी पेयजल एवं सीवर लाइन सहित मसूरी के सौंदर्यीकरण एवं विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी के सौंदर्यीकरण कार्यों को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत लाइनों एवं अन्य केबलों को अंडरग्राउंड करने के साथ ही मॉल रोड के पक्कीकरण का कार्य 20 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि टॉयलेट्स

आदि का निर्माण भी समय से पूरा कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि मसूरी पेयजल लाइन की टेस्टिंग का कार्य मार्च अंत तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल लाइन निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने हेतु 2 शिफ्टों में कराया जाए। गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीवर लाइन के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं अपर सचिव पेयजल उदयरज सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को रेंजर्स ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु को निर्देशित करते हुए कहा कि घोषणाओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाते हुए दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी / प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिनांक 23 मार्च, 2023 को वर्तमान सरकार का एक साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। पिछले 01 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा

राज्य के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। राज्य सरकार आगामी 10 वर्ष का रोडमैप तैयार कर उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य सरकार के 01 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उनके द्वारा 23 मार्च को रेंजर्स ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण घोषणायें की गयी है। घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से उतारा जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि आवश्यक कदम उठाते हुए 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी / प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जाए।

कहीं आप भी तो नहीं कर रहे खुशबू चौधरी जैसी गलती ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अगर आप ऑनलाइन जॉब ऑफर पाकर अपने डाक्यूमेंट्स शेयर करने वाले हैं तो रुक जाइये क्योंकि जो खुशबू के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। यूपी में नौकरी के नाम पर ई-मेल पर कागजात मंगवाकर फर्जीवाड़े की घटना सामने आई है जो चौकाने वाली है। ठगों ने पहले फर्जीवाड़े की रकम को पीड़िता खुशबू खाते में ट्रांसफर करवाया और फिर लोन भी करवा लिया। मामले की जानकारी मिलने पर खुशबू के

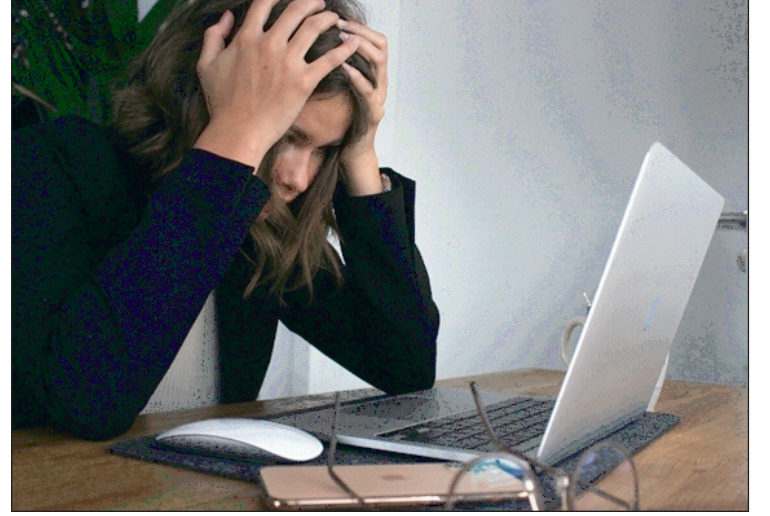
होश उड़ गए और वो अब भटकने को मजबूर है।

साइबर ठगों के द्वारा समय-समय पर नए तरीके अपनाकर लोगों को चूना लगाया जाता है। सामने आए ताजा मामले में पता लगा कि अब ठग नौकरी के नाम पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मेरठ से सामने आए केस में ठगों ने नौकरी के नाम पर एक युवती का आधार, पैन कार्ड समेत जरूरी कागजात ले लिए। इसके बाद जाली बैंक खाता खोलकर दो लाख रुपए का लोन भी ले लिया। वहीं

जब किस्त नहीं देने पर बैंक का कर्मचारी घर पहुंचा तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो सका।

नौकरी के नाम पर युवती ने मेल पर भेजे थे कागजात

मामले को लेकर युवती ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित खुशबू चौधरी ने जानकारी दी कि उसके पास जुलाई 2022 में नौकरी के लिए एक फोन आया था। फोन करने वाले युवक ने उससे कागजात मेल पर मंगवाए। इसके बाद कोई



जवाब नहीं आया। नौकरी को लेकर जब खुशबू ने युवक के नंबर पर दोबारा फोन किया तो कोई जानकारी ही नहीं मिली। दिसंबर 2022 में जब राजस्थान के कंकरखेड़ा थाने की पुलिस उसके घर पहुंची तो वह भी हैरान रह गई।

बैंक कर्मचारियों ने लोन के बारे में दी जानकारी

पुलिस ने बताया कि राजस्थान के एक बैंक में उसके नाम से खाता खुला है। ठगों ने उसी खाते में रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। हालांकि खुशबू ने ऐसे किसी भी

खाते की जानकारी से साफ इंकार कर दिया। वहीं इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने उसे जानकारी दी कि खाते पर 2 लाख का लोन भी लिया गया है। इसकी किस्त न जमा होने पर ही उन्होंने खुशबू से संपर्क किया। यह सब जानकर खुशबू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पीड़िता ने मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। आप भी ऐसे किसी गिरोह के जाल में न फंस जाए इसके लिए अपने कागजात को किसी अजनबी से साझा बिलकुल न करें।



बाप रे ! अय्याश बाबू ने कॉलगर्ल्स पर लुटा दिया कलेक्टर का बजट !



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 25 मार्च, खबर एक डीएम दफ्तर की है, एक जिला, एक प्रदेश की है लेकिन सच्चाई पूरे सिस्टम की है। सरकारी दफ्तरों के बाबूगिरी में ऐसे लोग ही जनता का भरोसा तोड़ते हैं जिनको जिम्मेदारी समाज का भला करने की दी जाती है। मामला इंदौर कलेक्टर का है जहाँ घोटालेबाज करोड़पति बाबू मिलाप चौहान पकड़ा गया है। विभाग के लोगों ने उसकी पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मिलाप सहित कुल 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान उसकी कई हवाई यात्राओं की जानकारी मिली है। उसने कई कॉल गर्ल और गर्लफ्रेंड को भी पैसे ट्रांसफर किये हैं। ये है पूरा मामला - इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने हाल ही में

सरकारी पैसे में बड़ी हेराफेरी पकड़ी थी। यह राशि की हेरफेर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर कार्यालय का ही बाबू मिलाप चौहान था। शुरुआती वक़्त में लगभग एक करोड़ रुपये की राशि के गबन का अनुमान था। लेकिन दो या तीन दिन में ही यह आंकड़ा पांच करोड़ के पार पहुंच गया।

कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू मिलाप चौहान पर करोड़ों के गबन के गंभीर आरोप हैं। वह 12 वीं पास है और अनुकम्पा नियुक्ति पाकर नौकरी में आया था। उसने सरकार के लेखा अफसरों की अनदेखी का भरपूर फायदा उठाया। हितग्राही मूलक योजना में जो आवेदन रह होकर या तकनीकी खामी के कारण पैसा वापिस आ जाता था उस पैसे को मिलाप अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर करता रहा।

कलेक्टर कार्यालयों में काफी बजट रहता है। वहां से अलग-अलग मदों में इस राशि का भुगतान होता ही है। और भुगतान की जिम्मेदारी मिलाप के ही पास थी। भुगतान के दौरान कई ऐसे खाते होते थे, जिनमें राशि ट्रांसफर नहीं हो पाती थी। मिलाप उस राशि को अपने खाते के अलावा एक अन्य बाबू, एक भृत्य, अपनी पत्नी सहित 29 लोगों के खाते में ट्रांसफर कर रहा था। पूछताछ में मिलाप ने अफसरों को यह भी बताया कि वह खाताधारकों को कुछ राशि भी देता था। और वह सभी को भरोसा भी दिलाता था कि यह कोई घोटाले गबन की राशि नहीं है।

कॉलगर्ल का शौकीन बाबू

पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद घोटालेबाज बाबू मिलाप चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस का अब हर संभव प्रयास है कि गिरफ्तार आरोपी से गबन की राशि वसूल की जा सके। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपनी गबन की राशि, सम्पत्ति और सैर सपाटे में खर्च करने की बात स्वीकार की है। जांच के दौरान उसकी कई हवाई यात्राओं की जानकारी मिली है। उसने कई कॉल गर्ल और गर्लफ्रेंड को भी पैसे ट्रांसफर किये हैं। पुलिस को आशंका है कि यह घोटाला और अधिक भी बढ़ सकता है। और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।



संपत्ति से जुड़े अपने ये अधिकार नहीं जानती हैं औरतें

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 25 मार्च, भारत में लड़कियों की परवरिश कुछ इस तरह की जाती है कि शादी से पहले उन्हें सिखाया जाता है कि उनका अपना घर कोई और होगा। और शादी के बाद ये जताया जाता है कि वो किसी और घर से आई हैं। इन दोनों नैरेटिव्स के बीच उलझी कई औरतें अपने फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी राइट्स जान नहीं पाती हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि एक औरत के पास प्रॉपर्टी के कौन-कौन से अधिकार होते हैं।

मायके की संपत्ति पर महिला का अधिकार

इसके दो पहलू हैं। पहला अगर संपत्ति खुद अर्जित की हुई संपत्ति है। इस केस में अगर किसी व्यक्ति की मौत बिना किसी वसीयत के हो जाती है तो संपत्ति उसके बेटों और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी। इसके साथ ही अगर मरने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी जीवित हैं, या उनकी मां हैं तो उनको भी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। पर अगर वो व्यक्ति अपनी वसीयत बनाकर किसी एक बच्चे को, या किसी अजनबी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी, कोई और उस पर अधिकार नहीं जता सकता है।

दूसरा पहलू है पैतृक संपत्ति का। पैतृक संपत्ति पर अधिकार जन्म से तय होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में पहले घर में पैदा होने वाले बेटों को संपत्ति पर अधिकार मिलता था, बेटियों परिवार की सदस्य मानी जाती थीं, जिनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी परिवार की होती थी। शादी के बाद परिवार में बेटों की सदस्यता खत्म हो जाती थी और उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की हो जाती थी। 2005 में

कानून में बदलाव किया गया।

ससुराल की संपत्ति पर महिला का अधिकार

यहां भी दो पहलू हैं। पहला अगर संपत्ति पति की कमाई हुई है। इस केस में पत्नी पति की क्लास वन एअर होती है। क्लास वन एअर में पत्नी, बच्चे, मां आते हैं। यदि किसी शख्स की बिना वसीयत के मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके सभी क्लास वन एअर्स में बराबर बंटती है। पर अगर वो शख्स वसीयत में किसी को अपना वारिस बनाकर जाता है तो वो प्रॉपर्टी उसके वारिस को ही मिलेगी।

तलाक की स्थिति में महिला के अधिकार
अगर एक महिला अपने पति से अलग होना चाहती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत वो पति से अपना भरण पोषण मांग सकती है। ये भरण पोषण पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है। ये तलाक का वन टाइम सेटलमेंट भी हो सकता है और मासिक भत्ता भी। तलाक के समय ही तय हो जाता है कि एकमुश्त एलिमनी दी जाएगी या मासिक भत्ता।

स्त्रीधन पर अधिकार

एक महिला को शादी से पहले, शादी में और शादी के बाद गिफ्ट में जो भी कैश, गहने या सामान मिलता है, उन सब पर महिला का ही पूरा अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 ये अधिकार देते हैं। अगर उसे उसके इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो महिला डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 19ए के तहत पुलिस में शिकायत कर सकती है।



रुद्रप्रयाग और हरिद्वार ईको टूरिज्म की दृष्टि से काफी संभावनापूर्ण : मुख्य सचिव

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 25 मार्च मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने प्रदेश में ईको टूरिज्म और जड़ी-बूटी को बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 70 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण वन प्रदेश की आर्थिकी का महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों को आर्थिकी से जोड़ने की आवश्यकता है। हम वनों एवं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ईको टूरिज्म और इनसे प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिकी को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि ईको टूरिज्म की भांति जड़ी-बूटी को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में, जहां भी सम्भव हो, हर्बल विलेज स्थापित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की संभावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। हितधारकों से संवाद स्थापित कर के इस कार्य में आ रही समस्याओं और उनके निराकरण पर कार्य



किया जाए। इसमें वन पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को साथ लेकर जड़ी बूटियों का उत्पादन 100 गुना या इससे भी अधिक बढ़ाए जाने की दिशा पर प्रयास किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि जड़ी बूटी के

लिए रवन्ना व्यवस्था के सरलीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए शीघ्र ही केन्द्र सरकार के नेशनल ट्रांजिट पास से इसे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियों के उत्पादन और चुगान के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की

जाए। उन्होंने इसके लिए पूर्व के शासनादेशों का सरलीकरण भी किए जाने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों को आसान किया जा सके। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ जनपद स्तरीय समितियों की वित्तीय एवं अन्य शक्तियों को बढ़ाया जाएगा।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ईको टूरिज्म से सम्बन्धित पिछली बैठक में बाकी बचे जिलों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म और वनों से प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर रोजगार सृजन किया जा सकता है। उन्होंने रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जनपद को ईको टूरिज्म की दृष्टि से काफी संभावनापूर्ण बताया। कहा कि केदारनाथ में मौसम खराब या भीड़ अत्यधिक होने के कारण यात्रियों को लंबे समय तक रुकना पड़ जाता है। ऐसे में इन यात्रा मार्गों के आसपास विकसित किए जाने वाले छोटे-छोटे ईको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हरिद्वार में भी तीर्थ यात्रियों को आसपास के क्षेत्र में ही ईको टूरिज्म और हर्बल पार्क पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों से लगे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मुख्य सचिव ने चकराता वन प्रभाग में बनाए गए ईको टूरिज्म और ट्रेकिंग सर्किट 'थंडियार मार्च' के प्रस्तुतीकरण को देखकर इसी की तर्ज पर अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के सर्किट विकसित किए जाने की बात कही। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु एवं सचिव डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम आवास में हुआ 22 दिन में 40 किलो शहद उत्पादन



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 25 मार्च, मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद प्रसंस्करण का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 22 दिनों के अन्तराल में लगभग 40 किग्रा शहद का

उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मौनपालन को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौनपालन को बढ़ावा

देने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य अजय सैनी ने मौनपालन के सम्बन्ध में जानकारी दी। उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित ने शहद प्रसंस्करण की जानकारी दी।

जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में किताबों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक पहल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 25 मार्च : जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा किताबों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत उपयोग में न आने वाली किताबों को जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु दान किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कई लोगों के पास धन की उपलब्धता न होने के फलस्वरूप विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, देहरादून ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसमें सक्षम लोग अपनी अनुपयोगी किताबों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जिला प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि अपनी अनुपयोगी किताबों को दान कर इस मुहिम में अपना योगदान दें। उन्होंने बताया कि देहरादून स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें, दून लाइब्रेरी (लैसडौन चैक), एमडीडीए ऑफिस



(ट्रांसपोर्ट नगर), देहरादून स्मार्ट सिटी ऑफिस (कौलागढ़ रोड, राजेंद्र नगर), वात्सल्य डे केयर सेंटर, तिलु रौतेली भवन (सर्वे चैक) आप दिए गए पते पर अपनी अनुपयोगी किताब को पहुंचा सकते हैं। अभी तक दूनवासियों द्वारा 250 से अधिक पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। प्राप्त की गई किताबों को जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा।

पर्यटन ग्राम तिवाड़ गांव में बर्ड वाचिंग शिविर शुरू

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नई टिहरी। होमस्टे आच्छादित पर्यटन ग्राम घोषित जनपद के मरोड़ा के तिवाड़ गांव में शुक्रवार से बर्ड वाचिंग के 4 दिवसीय शिविर की शुरुआत की गई है। शिविर में विश्व प्रसिद्ध बर्ड वाचिंग ट्रेनर अजय शर्मा व अश्विन त्यागी स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर इसके व्यवसायिक उपयोग से अवगत करायेंगे। उन्होंने बर्ड वाचिंग की संभावनाओं को लेकर भी युवाओं को पहले दिन जानकारी दी। तिवाड़ गांव के युवा पर्यटन व्यवसायी थौलधर ब्लाक के पूर्व कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप पंवार ने बताया कि तिवाड़ गांव में बर्ड वाचिंग शिविर से पर्यटन के क्षेत्र में एक ओर पहल शुरू होगी। उन्होंने इसके लिए अजय शर्मा व अश्विन त्यागी का आभार जताते हुए कहा कि बर्ड वाचिंग शिविर की शुरुआत की गई है। क्षेत्र के युवाओं को इस शिविर में प्रतिभाग के लिए आमंत्रित किया गया है। बर्ड वाचिंग की विधा को रोजगार का जरिया बनाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। युवाओं को इसे समझना व जानना होगा। बताया कि अब

तक युवाओं व महिलाओं ने कुल 33 से अधिक रजिस्ट्रेशन शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए करवाये हैं। बर्ड वाचर शर्मा व त्यागी ने शुक्रवार सुबह 7 बजे से गांव में 2 टीमों के साथ गांव में बर्ड वाचिंग का प्रशिक्षण शुरू करवाया। पूरे गांव में भ्रमण कर बर्ड वाचिंग युवाओं व महिलाओं को करवाई। इस दौरा 21 से अधिक पंछियों की पहचानकर फोटो लेकर जानकारी दी। अजय शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन में बर्ड वाचिंग में बढ़ी संभावना है। इसमें स्वरोजगार से जुड़ने का बड़ा मौका है। पूर्व कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप पंवार ने कहा कि गांव के लोग काफी संख्या रूचि लेकर कोर्स कर रहे हैं। इससे पर्यटकों को ज्यादा समय तक गांव में रोकने का मौका मिलेगा। शिविर में ग्राम प्रधान संगीता देवी, पूर्व प्रधान विजय पाल नेगी, विनोद रावत, साकम्बरी देवी, नरेंद्र रावत, सुरवीर सिंह, जयेंद्र सिंह, अनिता देवी, सुमित्रा देवी, साब सिंह, लक्ष्मी देवी, विपिन पंवार, नमन कंसवाल, गौरव, मूर्ति पुंडीर, अंजली, दिवंगी, दीपा देवी आदि मौजूद रहे।

एक पहल शिक्षा के नाम

अपने अनुपयोगी किताबों को जरूरतमंदों को दान करें

कई लोगों के पास धन की उपलब्धता न होने के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, देहरादून ने एक पहल की शुरुआत की है, जिसमें आप अपने अनुपयोगी किताबों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। अपनी अनुपयोगी किताबों को दान कर इस मुहिम में अपना योगदान दें

भेंट करने का स्थान:
देहरादून स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें, दून लाइब्रेरी (लैसडौन चैक), एमडीडीए ऑफिस (ट्रांसपोर्ट नगर), देहरादून स्मार्ट सिटी ऑफिस (कौलागढ़ रोड, राजेंद्र नगर), वात्सल्य डे केयर सेंटर, तिलु रौतेली भवन (सर्वे चैक) आप दिए गए पते पर अपनी अनुपयोगी किताबों को पहुंचा सकते हैं।

जल्द मिलेगी गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिंग होम की सुविधा : डॉ. आर राजेश कुमार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 25 मार्च प्रदेश को शीघ्र ही मिलेंगे गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिंग होम की सुविधा यह बात डॉ. आर राजेश कुमार सचिव स्वास्थ्य व मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) उत्तराखंड की बैठक में निर्णय लिया गया।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व बर्थ वेंटिंग होम में राज्य के समस्त 13 जनपदों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर एवं वकिंग वुमेन हॉस्टल में रखे जाने हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय देखभाल समय पर प्राप्त होगी व प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं को सहूलियत होगी। साथ ही होम डिलीवरी को संस्थागत प्रसव में प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेंटिंग होम में उपयोग किये जाने हेतु भारत सरकार ने मंजूरी दी है। यह कदम मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि बजट में जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल को मोबाइल टीबी वैन एवं टूनेट मशीन की सुविधा हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है व जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी को मोबाइल एक्स-रे के साथ



चिकित्सा और पोषण चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाएगी। सचिव द्वारा बताया गया कि प्रदेश को मोतियाबिंद बैकलॉग मुक्त बनाने के लिए मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग हेतु टिहरी एवं पिथौरागढ़ जनपदों को मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही उप जिला चिकित्सालय मसूरी में नेत्र सर्जरी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण है। इसके महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था जिसको मंजूरी मिल चुकी है। इसमें अब चिकित्सक अपने ड्यूटी के बाद दोपहर 3 बजे से साय 6 बजे तक टेली

कंसल्टेशन के माध्यम से जनमानस को सुझाव परामर्श देंगे जिस हेतु चिकित्सकों को प्रत्येक रोगी देखने पर 150 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा ऐ.एन.एम. एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चमोली जनपद में पूर्व से ही मौजूदा बिल्डिंग में एन.एच.एम. ऑफिस एवं प्रशिक्षण हॉल की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पताल में लम्बी कतार के बेहतर प्रबंधन हेतु 14 अस्पतालों में टोकन की सुविधा की स्वीकृति

मोबाइल मेडिकल यूनिट में सहमति बनी है जिससे टी.बी के मरीजों की स्क्रीनिंग करने में आसानी होगी। टी.बी. से ग्रसित मरीज एवं उनके परिवार जन के एक्स-रे के लिए निःशुल्क आवागमन की सुविधा हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति भी दी गई है।

1 माह से 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एन.आर.सी.) पिथौरागढ़ को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर मानदंडों के अनुसार



अब हर माँ और शिशु को मिलेगी निःशुल्क सेवाएं

सुदक्षित मातृत्व आश्रम "सुमन" अभियान
के अंतर्गत निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाएं।

अगर कोई असुविधा हो,
तो कॉल: **104**

भी दी गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भूपतवाला में 100 प्रतिशत रिक्त पदों की के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भर्तियों की स्वीकृति भी पारित हुई है।

नीति आयोग ने यूएसनगर को दी 3 करोड़ के प्रपोजल की मंजूरी



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 25 मार्च, आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग की ओर से 38वीं बैठक में जनपद के पुरस्कृत राशि हेतु प्रस्तुत किए गए प्रपोजल की समीक्षा कर अप्रूव किया गया। जनपद में कृषि विभाग के द्वारा 3 करोड़ का प्रपोजल दिया गया जिसकी थीम "उधम सिंह नगर में सतत और समावेशी कृषि को बढ़ावा देना"

(Promoting Sustainable and Inclusive Agriculture in Udhham Singh Nagar) के आधार पर किया गया।

जनपद की ओर से मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा द्वारा प्रपोजल को नीति आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप नीति आयोग ने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। मुख्य

विकास अधिकारी के द्वारा इस प्रपोजल के क्रियान्वयन एवं रिव्यू हेतु एक कमेटी गठित करने को कहा जो कि समय समय पर इसका रिव्यू करती रहेगी। बैठक में प्रशिक्षु आईएस अनामिका, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जीमल, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा, पीरामल फाउंडेशन की ओर से डिस्ट्रिक्ट लीड आशीष भटनागर सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

25 मार्च के स्थान पर 27 मार्च को होगा बहुदेशीय शिविर का आयोजन

देहरादून। मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने अवगत कराया है सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 25 मार्च 2023 को विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत हाथीबडकला स्टेडियम देहरादून में बहुदेशीय शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु अन्य किसी कारण से बहुदेशीय शिविर का आयोजन 25 मार्च के स्थान पर अब दिनांक 27 मार्च 2023 को आयोजन किया जायेगा। यह भी अवगत कराया कि विधानसभा राजपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित अमरीक हॉल, रेसकोर्स गुरु गोविन्द सिंह चौक में 25 मार्च 2023 को बहुदेशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा राजपुर हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

पिटकुल में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के प्रमोशन के खुले रास्ते

देहरादून। पिटकुल में अब डाटा एंट्री ऑपरेटरों के भी भविष्य में प्रमोशन हो सकेंगे। इसके लिए मैनेजमेंट ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पद परिवर्तन के आदेश कर दिए हैं। इस पर ऊर्जा कामगार संगठन ने एमडी पीसी ध्यानी का आभार जताया। पिटकुल में वर्ष 2004 में नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों को मानचित्रक और आशुलिपिक तृतीय के पदों में बदल दिया गया है। इस आदेश के बाद अब डाटा एंट्री ऑपरेटरों की लम्बे समय से चली आ रही प्रमोशन की मांग पूरी होने के साथ साथ उनके कैरियर ग्रोथ का रास्ता साफ हो गया है। वर्ष 2007 में शासन ने पिटकुल में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के संवर्ग मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद कैरियर ग्रोथ बंद हो गई थी। कर्मचारियों को इसका वित्तीय नुकसान हो रहा था। संगठन की ओर से मैनेजमेंट पर लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा था। अब विधिवत आदेश होने पर संगठन प्रतिनिधिमंडल ने एमडी पीसी ध्यानी को बुके भेंट कर उनका आभार जताया। पिटकुल के विकास को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महाप्रबन्धक अशोक कुमार जुयाल, उपमुख्य कार्मिक अधिकारी विवेकानन्द पोखरियाल, अध्यक्ष विजय बिष्ट, कार्यवाहक अध्यक्ष सोहन शर्मा, महामंत्री दीपक बेनिवाल, अमनेश धीमान, नीलम सेनी, मालती, फिरोज, जितेंद्र अरोरा, विजय, संजय गर्ग, हरेंद्र सिंह मौजूद रहे।

बेसबॉल में दून स्ट्राइकर और फरीदाबाद जीते

देहरादून। विनय विंडलास मेमोरियल अखिल भारतीय बेसबॉल क्लब प्रतियोगिता के दूसरे दिन दून स्ट्राइकर और फरीदाबाद ने जीत दर्ज की। देहरादून में परेड ग्राउंड में शुक्रवार को पहला मैच चंडीगढ़ मिशन क्लब वर्सेस और दून स्ट्राइकर के बीच खेला गया। इसमें दून स्ट्राइकर ने 10-01 से जीत दर्ज की। दून स्ट्राइकर की ओर से अभिषेक, मनीष, योगेश, सुमित ने 2-2 और सुखविंदर, गुरप्रीत ने 1-1 रन बनाए। दूसरे मैच में फरीदाबाद क्लब ने ग्रैंड स्लैम क्लब दिल्ली को 11-1 के अंतर से हराया। फरीदाबाद की ओर से बादली सागर, नीरज सागर 2-2 और विनायक सूरज और राज ने 1-1 रन बनाए। तीसरा मैच नाइन फेमस क्लब चंडीगढ़ और राजा रानी महाराष्ट्र के बीच हुआ। इसमें दोनों टीमों ने 5-5 रन किए। नाइन फेमस क्लब की ओर से दीपक ने दो, भूपेंद्र, राहुल, माली ने 1-1 रन बनाए।

सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा शानदार कार्य : गणेश जोशी

कृषि के क्षेत्र में विपणन के लिए सहकारी समितियों का अहम योगदान : गणेश जोशी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मसूरी, 25 मार्च, प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सम्मेलन में उत्तराखण्ड सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों के अधिकारीगण एवं प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विपणन के लिए सहकारी समितियों का अहम योगदान है। मंत्री ने कहा आज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की लाखों बहने लाभ ले रही हैं। देश में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की बजाय सहकारिता क्षेत्र सर्वोपरि है। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सामाजिक क्षेत्र होगा, जहां सहकारिताएँ कार्यरत नहीं हैं। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ देश की राष्ट्रीय, राज्य और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहकारी संघ का हिस्सा हैं, जो देश भर के तीस करोड़ से अधिक आबादी के जीवन को स्पर्श करती हैं। मंत्री जोशी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI)



देश में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्षस्थ संगठन है। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) देश में सहकारिता आंदोलन के शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम और

अन्य गतिविधियों हेतु शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि सहकारिता से जुड़े सदस्यों और कर्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए एनसीयूआई हाट' और इनक्यूबेशन केंद्र की भी स्थापना

की गई है। प्रदेश में ग्राम्य विकास के अधीन भी हमने इसी कर्ज पर रुरल इनक्यूबेशन (आरबीआई) की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाये हैं। मंत्री जोशी ने कहा केन्द्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश भर में सहकारिता पर बहुत शानदार कार्य हो

रहा है। मंत्री जोशी ने कहा कि सहकारिता ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और श्रम की शक्ति एक निश्चित उद्देश्य को लेकर एक दिशा में कार्य करती है और प्राप्त लाभांश को बराबर-बराबर बांटती है। इसी क्रम में सहकारी समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर भी सम्मेलन, सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य जोनल क्षेत्रों के राज्यों हेतु जोनल सम्मेलन का आयोजन मसूरी, उत्तराखण्ड में किया जा रहा है जिसमें सभी हितधारकों से विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा और नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा निश्चित ही इस सम्मेलन के माध्यम से जो मंथन निकलकर आएगा। वह प्रदेश के सशक्त उत्तराखण्ड के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ दिलीप संधणी, डा० चन्द्रपाल सिंह यादव, डा० सुनील कुमार सिंह, के. शिवदासन नामर, बिजेन्द्र सिंह बी. एल. मीणा, आदित्य चौहान, डा० सुधीर महाजन, रेशम फेडरेशन अध्यक्ष अजीत चौधरी, मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, मोहन पेटवाल, कुशल राणा सहित कई लोग उपस्थित रहे।

विधायक काऊ की अध्यक्षता में हुआ बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रदेश स्तर 'जन सेवा' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत समस्त विकासखण्डों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं इसी श्रृंखला में आज विकासखण्ड रायपुर क्षेत्रान्तर्गत शिव जूनियर हाईस्कूल देवा मालदेवता में मा० विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से अपने-विभाग से सम्बन्धित जानकारी जनमानस को दी गई। बहुउद्देशीय शिविर में पंचायतीराज विभाग, समाज कल्याण

विभाग, जल संस्थान, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गए थे। शिविर में माननीय विधायक रायपुर ने स्वास्थ्य जांच भी कराई।

माननीय विधायक रायपुर ने उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से जनमानस की समस्या का उन्हीं के क्षेत्र में निस्तारण हो इसके लिए उन्हें भटकना न पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रदेश के विकासखण्ड स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजित किये जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारी क्षेत्र की

समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करें तथा क्षेत्रों में भ्रमण करें जिससे क्षेत्रवासियों को अपने ही क्षेत्र में समस्याओं का समाधान मिले अनावश्यक कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, खण्ड विकास अधिकारी चक्रधर सेमवाल सहित पंचायतीराज विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल संस्थान, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग आदि विभागों के अधिकारी/कर्मिक मौजूद रहे। इस अवसर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

पौड़ी परिसर में छात्रों को पानी की टेस्टिंग की दी जानकारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में पानी की गुणवत्ता और उसकी टेस्टिंग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला यूकॉस्ट और रसायन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यशाला में परिसर के सौ से अधिक छात्रों को पानी की टेस्टिंग के बारे में भी बताया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) की इस कार्यशाला में जल संस्थान के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। जल गुणवत्ता अनुश्रवण और प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला में जल की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया। परिसर निदेशक प्रो. पीपी बडोनी ने बतौर मुख्य अतिथि ने जल के धार्मिक महत्व को बताया। कहा कि ग्रंथों और पुराणों में जल के महत्व का वर्णन है और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक मनुष्य जल से जुड़ा रहता है। यूकॉस्ट के जिला समन्वयक प्रो. डॉ. प्रशांत सिंह ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इन उत्तराखण्ड अंडर पीएमएयू विषय पर बोलेते हुए मानव अस्तित्व और जीवन के संदर्भ में पानी की महत्व के बारे में बताया। कहा कि पेयजल स्रोतों के लगातार अनुश्रवण और प्रबंधन से ही जल की गुणवत्ता में सुधार किया जा

सकता है। राज्य के पेयजल स्रोतों का पीएमयू के माध्यम से लगातार वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कई प्राकृतिक स्रोत जो सूख गए हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यशाला में प्रो. उमेश चंद्र गैरोला ने कहा कि जीवन के आवश्यक तत्वों में पानी एक प्रमुख है। इसकी बर्बादी रोकने के प्रयास जरूरी हैं। प्रो. पीपी बडोनी ने नमामि गंगे: एन इंटीग्रेटेड मिशन टू कंजर्व मदर गंगा इन उत्तराखण्ड विषय पर विस्तार से बताया। कार्यशाला के तकनीकी सत्र में उत्तराखण्ड जल संस्थान, उपप्रयोगशाला सतपुली के कैमिस्ट मुकेश व फील्ड मैनेजर रजत मैठाणी ने प्रतिभागियों को फील्ड टेस्टिंग किट के जरिए जल गुणवत्ता जांच की तकनीकियां बताईं। इस दौरान 10 रासायनिक व जैविकीय जल गुणवत्ता मानकों की टेस्टिंग सही तरीके से करने की पूरी जानकारी दी गई। कार्यशाला में परिसर के सौ से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर प्रो. उमेश चंद्र गैरोला, प्रो. एमसी पुरोहित, डॉ. गौतम कुमार, डॉ. सुभाष गुप्ता, डॉ. रामप्रकाश, डॉ. सीबी कोटनाला, डॉ. मनीष उनियाल, डॉ. धर्मेन्द्र, डॉ. लवकेश, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. सरिता आदि भी मौजूद रहे।

केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में मौसम डाल रहा खलल

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लोनिवि डीडीएमए द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी है। हालांकि लगातार खराब मौसम केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में खलल डाल रहा है। शुक्रवार को भी मौसम ने मजदूरों के हाथ रोक दिए। बर्फबारी के कारण मजदूरों का काम प्रभावित हुआ। ठीक एक महीने बाद भगवान केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट देश-विदेश के तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इस लिहाज से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागों को यात्रा तैयारियों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं किंतु लगातार बारिश और बर्फबारी से यात्रा तैयारियों में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। लोनिवि डीडीएमए ने पूर्व में केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोड़े-खच्चरों की आवाजाही करा दी थी किंतु बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से पैदल मार्ग पर छोड़े-खच्चरों की आवाजाही बंद हो गई है। केदारनाथ, लिंचौली, भीमबली आदि स्थानों से मजदूर लगातार बर्फ हटाते हुए रास्ता तैयार कर रहे हैं किंतु लगातार हो रही बर्फबारी से मजदूरों के हाथ रुक रहे हैं।

सहरी में इन चीजों का करे सेवन, दिन भर नहीं लगेगी भूख और प्यास



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 25 मार्च, रमजान के महीने के दौरान अधिकांश मुसलमानों को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच खाने-पीने से पूरी तरह परहेज करना होता है। रमजान के दौरान आप क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते हैं, इससे आपके ऊर्जा स्तर पर बहुत फर्क पड़ता है। पूरे दिन उपवास के बाद, अक्सर इफ्तार और सहरी के दौरान मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन

करने का प्रलोभन होता है, लेकिन आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपवास शुरू करने से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार करना सबसे अच्छा है। पहले 2 या 3 दिन सबसे कठिन होंगे। जैसे-जैसे आप उपवास में गहरे और गहरे होते जाएंगे यह आसान और आसान होता जाएगा। आपको

पहले कुछ दिन उपवास करने में कठिनाई हो सकती है और दिन में भूख महसूस हो सकती है। यह सामान्य है और समय के साथ आपका शरीर नई घड़ी के अनुकूल हो जाएगा। फलों के अलावा आपको सूखे मेवे जैसे खजूर, अखरोट और बादाम भी बेहतरीन फूड सप्लीमेंट हैं। वे आपको पूरे



दिन लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकते हैं। इफ्तार के लिए फल और सब्जियां, साबुत ब्रेड, ब्राउन राइस या साबुत अनाज नूडल्स जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जो शरीर को ऊर्जा, फाइबर और खनिज प्रदान करते हैं। आप अपनी डाइट में दही, दाल, हरी सब्जी, फल, कच्चा पनीर शामिल कर सकते हैं।

सहसपुर में हुआ बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रदेश स्तर 'जन सेवा' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत समस्त विकासखण्डों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज विकासखण्ड सहसपुर नगर पंचायत अन्तर्गत नगर पंचायत सेलाकुई में माओ विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुण्डरी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से अपने-विभाग से सम्बन्धित जानकारी जनमानस को दी गई। बहुउद्देशीय शिविर में 25 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें पंचायतीराज विभाग के 8, जल संस्थान के 1, कृषि के 6, राजस्व विभाग से 10 शिकायत प्राप्त हुई। सभी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में 69 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन के 49, विधवा पेंशन के 14 दिव्यांग पेंशन के 6 आवेदन प्राप्त हुए जिनकी अभिलेखीय प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। इस अवसर पर पंचायतीराज विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल संस्थान, खाद्यी ग्रामोद्योग, उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गए थे।



तक विकास पहुंचाने की है, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय विधायक ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को प्रमुखता से सरकार के मध्य रखकर उनका निस्तारण करवाना है। इसके लिए वे संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारी क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बहुउद्देशीय शिविर में प्राप्त आवेदनों त्वरित प्रक्रिया करते हुए पात्र लाभार्थियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं आवेदनों पर

नियमानुसार कार्यवाही करें, जिससे जनसामान्य को अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु भटकना न पड़े।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अधिकरण आर सी तिवारी, आशीष बहुगुणा, मनीष कुकरेती, एडीओ समाज कल्याण पूजा पाल, सहित समस्त विभागों के अधिकारी सम्मिलित कार्मिक एवं पूर्व प्रधान भगत सिंह राठौर, पूर्व प्रधान विजयपाल, मंडल अध्यक्ष पंकी देवी, मंडल महामंत्री निखिल गुंसाई, नरगिस कश्यप, विनोद पाल, अरुण प्रकाश, ममता ठाकुर, शांति प्रभा, सुषमा पुरोहित, कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रतिनिधि अनिल नौटियाल ने किया।

जी-20 सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी

चमोली। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में भारत में होने जा रहे जी-20 सम्मेलन के मध्यनजर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी चमोली डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कहा कि हमें विज्ञान के साथ-साथ दादी-नानी के नुस्खों को भी अपनाना चाहिए, जिससे हमारा प्राचीन विज्ञान जीवित रह सके। कार्यशाला के मुख्य वक्ता संयुक्त मजिस्ट्रेट चमोली डॉ. दीपक सैनी ने कहा कि आज भारत का विश्व में मान बढ़ा है जो हमारे लिए गर्व का विषय है और उत्तराखंड राज्य हमारी देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है। जो संपूर्ण विश्व को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि जी 20 देशों की उत्पत्ति, उद्देश्य एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रो. रचना नौटियाल ने कहा कि यदि हमें विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपनी स्थानीय उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। कार्यक्रम के सहसंयोजक डॉ. मनोज बिष्ट ने भारत को जी 20 देशों की अध्यक्षता मिलने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए इसके दूरगामी वैश्विक प्रभावों से अवगत कराया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. जगमोहन नेगी ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जी 20 सम्मेलन में गोपेश्वर महाविद्यालय सक्रिय भूमिका अदा करेगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दर्शन सिंह नेगी ने किया। इस मौके पर प्रो. एमके उनियाल, प्रो. बीसी शाह, डॉ. मनीष डंगवाल, डॉ. बीपी देवली, डॉ. एसएस रावत, डॉ. डीसी सती, डॉ. गिरधर जोशी, डॉ. अरविंद भट्ट, डॉ. प्रियंका उनियाल डॉ. भावना मेहरा, डॉ. एके सैनी, डॉ. मनोज नौटियाल, डॉ. एस पी उनियाल, डॉ. एसके सैनी, डॉ. एसएल बटियाटा, डॉ. चन्द्रेश जोगेला, डॉ. दिगपाल कण्डारी, डॉ. विनीता नेगी, डॉ. विधि ध्यानी, डॉ. हर्षि खंडूड़ी, डॉ. बबिता, डॉ. रूपिन, डॉ. समीक्षा आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

उपकेंद्रों से पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े

देहरादून। विश्व टीबी दिवस के मौके पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से दून के दो स्वास्थ्य उप केंद्रों को जोड़ा गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डा. मनोज वर्मा के मुताबिक शमशेरगढ़ व कौलागढ़ में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से डॉक्टर, स्टाफ एवं मरीज जुड़े। मरीजों को टीबी के प्रति जागरूक किया गया और अच्छा खाना खाने एवं एहतियात बरतने की अपील की गई।

रायपुर रोड पर कल लगेगा बुक एक्सचेंज में मेला

देहरादून। नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (एनएपीएसआर) की ओर से 26 मार्च को बुक एक्सचेंज मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला साहनी मार्केट में बुक बैंक के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बैंक के संस्थापक आरिफ खान ने बताया कि जिस तरह से हर साल फीस बढ़ रही है, उससे अभिभावकों को अपने बच्चे पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में बुक बैंक की ओर से अभिभावकों के आर्थिक और मानसिक बोझ कम करने के लिए नित नए प्रयास किये जाते हैं। अपनी मुहिम मिशन फ्री एजुकेशन के अंतर्गत इस माह 26 मार्च को बुक एक्सचेंज मेले का आयोजन साहनी मार्केट रायपुर रोड स्थित बुक बैंक में किया जा रहा है। जिसमें अभिभावक अपनी किताबें आपस में आदान-प्रदान कर सकेंगे। साथ ही एसोसिएशन की ओर से 51 बच्चों को निःशुल्क स्टेशनरी भी वितरित की जाएगी और जरूरतमंदों के लिए कपड़ों का भी स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें से कोई भी जरूरतमंद अपनी पसंद का कपड़ा निःशुल्क ले जा सकेंगे।

31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह

देहरादून। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का वे शुभारम्भ करेंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अफसरों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि 31 मार्च को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ करेंगे। प्रदेश में 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसका शुभारम्भ केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ऑनलाइन करेंगे। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश की 95 एमपैक्सों में जन सुविधा केन्द्र एवं जन औषधी केन्द्रों की स्थापना का शुभारम्भ भी किया जाएगा। कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत शून्य ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वालों चैक दिए जाएंगे। सभी 95 ब्लॉक में एनसीडीसी के तहत संयुक्त सहकारी खेती के संचालन का भी शुभारम्भ किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा धामी सरकार का एक साल

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूर्ण होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। यह राज्य मातृशक्ति की देन है और राज्य की 50 लक्ष आबादी महिलाओं की है। वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आवास, शिक्षा, उद्यमिता में महिलाओं ने प्रभावी विकास यात्रा की है। राज्य में महिलाओं के लिए 30 लक्ष शैक्षणिक आरक्षण, लखपति दीदी योजना, घस्यारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा सफलता से संचालित की जा रही हैं।

डोईवाला में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं माननीय जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज " शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला, देहरादून" में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विर में सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव, द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, पोक्सो अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान,



माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के सम्बंध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। उक्त शिविर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0 ए0 एस0) के 09 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, उनके द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित

किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक सेवा के सम्बंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। उक्त शिविर में 13 मई 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पैम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया। अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई0मेल- पर सम्पर्क कर सकता है। शिविर में यह भी अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु ऑफलाइन सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लॉगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा ऑफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हैं। शिविर/कार्यक्रम के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी सक्रिय योगदान दिया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 व्यक्ति लाभान्वित हुए। शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।

मकान बेचने की डील कर एसओ से ठग लिए सवा लाख रुपये

देहरादून। उत्तराखण्ड पुलिस के दरोगा से बलवीर रोड स्थित मकान बेचने की डील कर दंपति ने 1.11 लाख रुपये हड़प लिए। मकान बेचने की डील 1.21 करोड़ में हुई। दरोगा ने मकान खरीदने के लिए बैंक में लोन के लिए आवेदन कर दिया था। इसके बाद उन्हें पता आरोपी इस तरह डील कर मकान के नाम अन्य लोगों से भी रकम ले चुके हैं।

अधिवक्ता राहुल राजवंशी ने बताया कि अरविंद कुमार उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक हैं। हाल में वह पौड़ी जिले के थाने के चार्ज पर हैं। पहले राजपुर थाने के एसओ रहे हैं। पिछले साल फरवरी में बलवीर रोड स्थित एक मकान को खरीदने के लिए उनकी डील तृप्ति शर्मा और उनके पति अजय कुमार शर्मा निवासी बलवीर रोड से हुई। दोनों ने मकान बेचने के लिए हामी भर दी। मौखिक रूप पर डील भी तय हो गई।

दरोगा ने टोकन के रूप में चेक के जरिए 1.11 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। मकान लेना था तो उन्होंने बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की। आरोप है कि इस बीच दंपति ने मकान रजिस्ट्री के नाम पर आनाकानी शुरू कर दी और उनकी रकम भी वापस नहीं की।

इस दौरान उन्हें पता लगा कि आरोपी दंपति ने ऐसा कई लोगों के साथ किया है। उन्होंने केस दर्ज कराने के लिए वकील राहुल राजवंशी के जरिए कोर्ट में अपील कराई। सीजेएम लक्ष्मण सिंह ने आरोपी दंपति के धोखाधड़ी संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश इस्पेक्टर डालनवाला को दिया है।

पुलिस मधुर और सौम्य व्यवहार का दे परिचय : नगन्याल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयाग। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करन सिंह नगन्याल ने जनपद रुद्रप्रयाग में पुलिस की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और कोतवाली में जाकर व्यवस्थाएं देखीं और वार्षिक निरीक्षण किया। शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने परेड अभ्यास का निरीक्षण किया गया। पुलिस कार्मिकों द्वारा की जा रही परेड की सभी टोलियों को बारीकी से देखा जबकि कमाण्ड एवं कण्ट्रोल को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। जनपद में स्थित केदारनाथ धाम की महत्ता विश्व स्तर पर है, यहां हर साल लाखों यात्री आते हैं इसलिए भी मधुर और सौम्य व्यवहार का परिचय दे। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी खयाल रखें। केदारनाथ यात्रा का सफल संचालन हमेशा ही एक चुनौती रहा है। ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो। उन्होंने सभी कार्मिकों को याद दिलाया कि वे सड़क दुर्घटना के दौरान मदद करने वाले गुड समरिटन व्यक्तियों के नाम अपने उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने थाना चौकी व शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी की साथ ही अपराध को लेकर जानकारी ली। थाने के मालखाने में कोई भी लम्बित माल न होने पर प्रसन्नता जताते हुए

थाना कार्यालय स्टाफ को 5000 का नगद पारितोषिक देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बार की यात्रा व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए युवा एवं अनुभवी कार्मिकों को मिश्रित रूप से तैनात किया जाएगा। कहा कि यात्रा में पुलिस बल के साथ ही एसडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस, पर्यटन पुलिस की तैनाती की जाएगी। मैदानी जनपदों से यहां पर पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पीएसी, आईआरबी की भी तैनाती होगी। जरूरत पडने पर कुमायूँ परिक्षेत्र से भी पुलिस तैनात की जाएगी। हेली सेवाओं के नाम पर होनी वाली धोखाधड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह के लालच में न आए। कहा कि अब तक इस वर्ष के यात्रा काल के लिए हेलीकोप्टर सेवाओं से सम्बंधित कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। बैठक में इससे पहले पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे ने पुलिस महानिरीक्षक को जनपद में हो रहे कार्य, केदारनाथ यात्रा तैयारी एवं पुलिस की प्रगति आदि की व्यापक जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे, पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार धिल्लियाल, पुलिस उपाधीक्षक, गुप्तकाशी विमल रावत, पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन्स हर्षवर्द्धनी सुमन, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन गणेश लाल बण्डवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग जयपाल सिंह नेगी, गोपनीय सहायक आईजी रेंज केएन चिलकोटी आदि मौजूद थे।

जल संरक्षण के लिए सबको करना होगा सहयोग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयाग। राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में नमामि गंगे परियोजना में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें वर्तमान परिदृश्य में जल संरक्षण के लिए आम जनमानस की सहभागिता एवं चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय गोष्ठी हुई। गोष्ठी में मुख्य अतिथि केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत ने कहा कि यह कार्यशाला हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार जल संरक्षण करना है। पहाड़ों में तो जल स्रोतों को पूजा जाता है। जो हमें प्रकृति के नजदीक लाता है। हमें फिर से इस संस्कृति को अपनाना होगा। उन्होंने महाविद्यालय को आश्चर्य किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वे प्रयासरत हैं। मुख्य वक्ता पाणी राखो आन्दोलन के प्रणेता एवं पर्यावरण रक्षक डा. सचिदानन्द भारती ने कहा कि पहाड़ों में जल संरक्षण के लिए वर्षा आधारित जल संग्रहण की योजना की बड़ी महत्ता है। हमें सामूहिक प्रयास से चाल खाल बनाने हैं और जल, जंगल और जमीन को बचाना है। स्पर्श गंगा प्रहरी से सम्मानित गढ़वाल केन्द्रीय विवि के पौड़ी परिसर

में कार्यरत प्रो. प्रभाकर बडोनी ने कहा कि हमें अपनी नदियों को न केवल व्यापक रूप से स्वच्छ और संरक्षित करना होगा। बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नदी के जलीय जीवन एवं जैव विविधता का संरक्षण भी हो। छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट ने केदारनाथ विधायक द्वारा महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए दिए गये सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि विधायक द्वारा महाविद्यालय को खनन न्यास से 55 लाख, विधायक निधि से 3 लाख पुस्तकालय के लिए तथा 2.70 लाख फर्नीचर हेतु दिया गया। जो कि एक वर्ष में किसी भी विधायक द्वारा दिया गया सबसे अधिक सहयोग है। मौके पर प्राचार्य प्रो. पुष्पा नेगी, डा. केपी चमोली, केदारनाथ नप के अध्यक्ष वेदप्रकाश सेमवाल, प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष विक्रम नेगी, कुलवीर रावत, राजेन्द्र नेगी, सुमन जमलोकी, डा. डीएस बिष्ट, डा. जितेन्द्र कुमार, डा. आबिदा, डा. ममता शर्मा, डा. निधि छाबड़ा, डा. ममता थपलियाल, डा. शशिला रावत, डा. सुनील भट्ट, डा. कनिका बड़वाल, डा. तनुजा मौर्य एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

संपादकीय



बेमानी होती वैश्विक संस्थाएं

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया में बहुपक्षवाद संकट में है। लगभग यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोहरायी है। गौरतलब है कि जब से भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली है, दुनिया में वैश्विक संस्थाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले द्वि-ध्रुवीय विश्व और बाद में अमरीका की अगुआई वाले एक-ध्रुवीय विश्व में भी वैश्विक संस्थानों की महती भूमिका मानी जाती रही है। संयुक्त राष्ट्र और उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाएं दुनिया के संचालन की धुरी बनी रहीं। कहीं द्वंद्व या संघर्ष हो या प्राकृतिक या मानव जनित आपदा हो, तमाम मुल्क संयुक्त राष्ट्र की ओर ही देखते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही नहीं, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि की विशेष भूमिका रही है। वर्ष 1995 से पहले 'गैट' और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को संचालित करने वाले नियमों के निर्धारक के रूप में जाने जाते रहे हैं। लेकिन आज इन संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धति तथा वैश्विक नेतृत्व की उनकी क्षमता पर ही नहीं, उनकी नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। महामारी, वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, दुनिया में बढ़ती खाद्य असुरक्षा और कई मुल्कों पर बढ़ते असहनीय कर्ज के कारण इन संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शासन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यही स्थिति संप्रभुता संकट, असंतुलन, संघर्ष और द्वंद्व, स्वतंत्र राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। जैसे समाधान इन संस्थानों से अपेक्षित है, वे उसमें असफल दिख रहे हैं। महामारी के शुरू से लेकर उसके निवारण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल नकारा ही साबित नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रमुख द्वारा चीन की तरफदारी करने के कारण बदनाम भी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन भी सम्मेलन और बैठक करने वाले संगठन बन कर रह गये हैं। विभिन्न मुल्कों का भी अब उन पर कोई विशेष विश्वास नहीं रह गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी के समय इसके प्रारंभ के बारे में भी निष्पक्ष राय नहीं दे सका। टीकाकरण के मामले में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ कमाने के लालच पर भी वह अंकुश नहीं लगा पाया। जब यह अपेक्षा थी कि महामारी के दौरान आवश्यक दवाओं, टीकों और उपकरणों पर पेटेंट स्थगित किये जायेंगे तथा सभी प्रकार के इलाज और टीके रॉयल्टी मुक्त उपलब्ध होंगे, पर व्यापार संगठन की 'व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार' (ट्रिप्स) काउंसिल में पहले तो कोई निर्णय ही नहीं हो पाया और बाद में भी केवल टीकों के संबंध में ही शर्तों के साथ हुए निर्णय ने संगठन की असंवेदनशीलता तथा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों की मानवता के प्रति उदासीनता को उजागर कर दिया।

दैनिक न्यूज़ वायरस

संपादक : मो.सलीम सैफी, कार्यकारी संपादक : आशीष कुमार तिवारी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मो.सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से प्रकाशित एवं न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून से मुद्रित। फ़ोन : 0135-4066790, 2672002 RNI No. : UT-THIN/2012/44094 Cert. Ser. No. : 31406 E-mail : dainiknewsvirus@gmail.com Website : www.newsvirusnetwork.com YouTube : TV News Virus न्याय क्षेत्राधिकार : जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड), भारत

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया 'एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन' में वर्चुअली प्रतिभाग



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। विश्व क्षय रोग दिवस (वर्ल्ड टीबी डे) के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी, उत्तरप्रदेश से 'एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन' को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत पहल: एक संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार (टीटीपी) की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने टीबी के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत किया।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनभागीदारी के सहयोग से इस अभियान में शामिल होकर टीबी रोगियों की सहायता का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल ने कहा कि हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रत्येक टीबी रोगी का निःक्षय मित्र बनकर उसके इलाज, पोषण में सहयोग करना होगा ताकि हमारा

प्रदेश टीबी मुक्त हो सके। उन्होंने प्रदेश के आम लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थानों आदि से आह्वान किया कि वे टीबी रोगियों की सहायता करने के लिए निःक्षय मित्र बनें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के साथ ही इसे जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य डॉ० आर. राजेश कुमार, अपर सचिव राज्यपाल स्वाति एस. भदौरिया एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

राजधानी देहरादून में दो साल में 34 फीसदी टीबी के मरीज बढ़े

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। देहरादून जिले में दो साल में 34 फीसदी टीबी के मरीज बढ़े हैं। लोगों में जागरूकता और कोरोना के बाद टीबी खोज अभियान के सक्रिय होने की वजह से ये मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। विभिन्न अस्पतालों में इनका उपचार चल रहा है। दून अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डा. मनोज वर्मा ने बताया कि 2020 में 3899, 2021 में 4520 मरीज चिन्हित किए गए और इनका इलाज शुरू हुआ। वहीं 2022 में 5918 मरीजों को टीबी की पुष्टि हुई। 2023 में अब तक ढाई महीने में 1113 मरीज मिल चुके हैं। उन्होंने बताया टीबी खोज अभियान को जिले में सक्रियता के साथ डोर टू डोर कैंपेन के साथ चलाया जा रहा है। कोरोना में मरीज कम अस्पताल आ रहे थे।

निजी डॉक्टर नहीं दे रहे जानकारी: चार सालों के डाटा में सामने आया कि निजी अस्पतालों में चिन्हित 20 प्रतिशत ही मरीज हैं। 80 फीसदी मरीजों की सूचना सरकारी अस्पतालों से मिली। विभाग कई बार निजी डॉक्टरों को नोटिस जारी कर चुका है।

दून अस्पताल में एमडीआर सेंटर अगले सप्ताह से: दून अस्पताल में टीबी एंड चेस्ट विभाग की ओर से गुरुवार को कार्यक्रम हुआ।

एचओडी डा. अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पांच साल में छह हजार मरीजों को यहां इलाज दिया गया। 700 एमडीआर के मरीज थे। टीबी एंड चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अनुराग अग्रवाल एवं डा. अविशम ने सभी प्रकार की टीबी, उनके लक्षण एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य डा. आशुतोष सयाना ने कहा कि एमडीआर टीबी के इलाज को सेंटर बन गया है। अगले सप्ताह मंत्री शुभारंभ करेंगे। इससे गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा। इस दौरान डीटीओ डा. मनोज वर्मा, डीएमएस डा. धनंजय डोभाल, डा. नारायणजीत सिंह, डा. दौलत सिंह, डा. अभिषेक चौधरी, डा. अविशम, डा. आकर्ष उनियाल, गालिब आदि मौजूद रहे।

एक मदरसा लेगा: दो मरीज गोद

मदरसा बोर्ड के डिट्टी रजिस्ट्रार की ओर से प्रदेश के सभी मदरसों के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र अभियान से जुड़ने को हर मदरसा दो दो मरीजों को गोद लेगा।

गोद लेने में दून आगे: निक्षय मित्र योजना के तहत दून में सहमत के बाद सभी 1900 मरीजों को गोद लिया गया है। तस्मिया अकादमी ने सर्वाधिक 150, बाला जी सेवा संस्थान और लायंस क्लब 100-100 मरीज सर्वाधिक गोद लिए हैं।

सीएम धामी ने की राज्यपाल से मुलाकात



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने आशा व्यक्त

की कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम एक श्रेष्ठ उत्तराखण्ड के निर्माण में अथक प्रयास जारी रखते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेंगे।

बेहतर काम करने वाले पांच सब स्टेशनों को मिलेगा प्रोत्साहन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। ऊर्जा निगम में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। बेहतर काम करने वाले पांच सब स्टेशनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उपभोक्ता सुविधाओं, सप्लाई सिस्टम में गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर समाधान किए जाने के निर्देश दिए।

सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर यूपीसीएल मुख्यालय में आयोजित संगोष्ठी में एमडी अनिल कुमार ने कहा कि

बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम किया जाए। उपभोक्ताओं की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर समाधान हो। उपभोक्ता सुविधा और पावर सप्लाई सिस्टम में बेहतर काम करने वाले पांच सब स्टेशनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सही काम न करने पर पांच सब स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

इसके लिए एक आंकलन सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस मौके पर एसई एनएस बिष्ट ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं, विभागीय इंजीनियर और लाइन स्टाफ को जागरूक करने का सुझाव

दिया। एसई विकास गुप्ता ने कहा कि बिजली से होनी वाली दुर्घटनाओं को कम करने पर जोर दिया। इसके लिए लाइन स्टाफ को और अधिक जागरूक करने के साथ ही ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। एसई अनिल धीमान ने कहा कि मोबाइल एप के जरिए उपभोक्ता सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने, कटवाने, बिलिंग समेत सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस अवसर पर निदेशक एमएल प्रसाद, अजय अग्रवाल, नवीन गुप्ता, राशिद अली जिलानी, डीएस खात्री, एमएल राणा, शिशिर श्रीवास्तव, सुधीर सिंह, मोहन मित्तल आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने किया वर्ष 2022 में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें व पुरतों के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रायपुर क्षेत्र में माह अक्टूबर 2022 में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें व पुरतों के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सौंग पुल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सौंग नदी के चैनेलाइज हेतु जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए एवं अन्य सभी आपत्तियों के निस्तारण हेतु शीघ्र शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा जिस भी क्षेत्र में अधिक कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है वहां पर भी सुरक्षा दीवारों का निर्माण हो एवं चैनेलाइज करने का कार्य तेजी से किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में आपदा के दौरान हुए नुकसान के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्य में तेजी से कार्रवाई हुई है। आज उन सभी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों से समीक्षा रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने कहा मानसून से पहले उन सभी क्षेत्रों / नदियों में जहां भी नुकसान होने की संभावना है उन क्षेत्रों में चैनेलाइज की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा मानसून से पहले पानी की निकासी, पहले से पड़े मलबे को हटाने एवं सुरक्षा दीवारों का कार्य प्राथमिकता से किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें के पुनर्निर्माण एवं रोड के नीचे सुरक्षा दीवार के निर्माण को अति शीघ्र किए जाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी सोनिका एवं अन्य लोग मौजूद रहे।